State Council be constituted to examine the recommendations. The Sub-Committee has so far held six meetings in the course of which 191 recommendations out of a total of 247 recommendations have been examined.

दिल्ली नगर निगम के लाजपत नगर स्थित कार्यालय में लगी आग से नष्ट हुई फाइलों की पुनर्रचना

2871. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के लाजपत नगर स्थित कार्यालय में आग लगने से नष्ट हुई अवैध निर्माण संबंधी फाइलों की पुनर्रचना का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्रचना का कार्य कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है ; और

(ग) सम्पूर्ण पुनर्रचना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण करने से संबंधित उन सभी 53 फाईलों का पुर्ननिर्माण कर दिया गया है, जो 2 फरवरी, 1993 को लगी आग में जल गई थीं ।

(ग) इसे पहले ही पूरा किया जा चुका है ।

2872. [*Transferred to 26th August, 1993.*]

Talks with the Authorities of the Closed Industrial Units in Jammu and Kashmir

2873. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government has started talks with the authorities of the closed industrial units in the Kashmir valley as part of the ongoing developmental activities in Jammu and Kashmir; and

(b) if so, what has been the progress in this regard; and

(c) whether some areas have been identified at the initial stage for starting the process; and

(d) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (d) As a part of the normalisation process, steps have been initiated to reactivate the economic and developmental activity including revival of close industrial units in Jammu and Kashmir. Discussions were recently held in Delhi and Srinagar with the concerned officials of the Central and State Governments and the financial institutions. The State Government has been asked to develop specific proposals in the light of these discussions so that work for revival of industrial activity can be pursued in a planned manner. Small scale industries, including units in the tourism sector, sericulture, handlooms, and handicrafts were identified as some of the important sectors for this purpose.

Present position with regard to holding Election in J & K

2874. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what is the present position with regard to holding elections in Jammu and Kashmir State to instal a popular Government; and

(b) what is the possibility of holding election in the State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) and (b) Government are keen to create conditions conducive for holding fair and free elections at the earliest. Towards this end, sustained efforts are being made to contain militancy and reduce the fear of the gun, activise the political elements and the local administration, step up development activities and motivate the people to come into the mainstream. The various steps taken in this direction have had a positive impact.

आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार

2875. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें कितने सरकारी कर्मचारी शामिल थे; और

(घ) सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) ।

(ग) और (घ) इस प्रकार के बलात्कारों में कर्मचारियों के लिप्त होने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कोई सांख्यकीय सूचना एकत्र नहीं की जाती है । जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी

जांच करना, पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है । जब कभी इस प्रकार की घटनाएं सूचित की जाती हैं तो वे उपयुक्त कार्रवाई करते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति अत्याचारों के मामलों में आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं ।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति की गई बलात्कार की घटनाएं

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	6
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	उ०न०
7.	हरियाणा	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	0
11.	केरल	13
12.	मध्य प्रदेश	217
13.	महाराष्ट्र	20
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	0
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	4
19.	पंजाब	0
20.	राजस्थान	32
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	0
23.	त्रिपुरा	0
24.	उत्तर प्रदेश	0
25.	पश्चिम बंगाल	1
		(जून, 1992 तक)
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0
29.	दमण और दीव	उ० न०
30.	दिल्ली	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	0

तिहाड़ जेल में यौन संबंधी अपराध

2876. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट" ने अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा है कि तिहाड़ जेल में महिला कैदियों के साथ बड़े पैमाने पर यौन अपराध की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की कोई जांच कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है; और

(ग) क्या जेलों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के पास कोई व्यापक योजना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनको ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है । दिल्ली प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि महिला कैदियों को पृथक वार्डों में रखा जाता है तथा उनकी निगरानी करने वाले स्टाफ में महिलाएं होती हैं ।

(ग) तिहाड़ जेल में स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रशासन द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिनमें अधिक जेलों का निर्माण करना, जल आपूर्ति बढ़ाना, सफाई की स्थिति में सुधार करना, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना शामिल है ।

Increasing Role of Army in Internal Security

2877. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Defence Ministry has expressed its serious concern at the increasing role of the army in internal security duties and about the deteriorating security system and dismal performance of the Central Police Organisations when deployed for internal security;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government with regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (c) Consequent to the Ministry of Defence offering certain suggestions about the prolonged deployment of Army on internal security duties, Ministry of Home Affairs have issued instructions to the State Govts. to ensure that Army's assistance is sought only as a last resort when, in their judgement, the situation is likely to go beyond the control of the State Police and the Units of the Central Police Organisations available with them.